

कार्ड की प्रति संलग्न की जाती है तो वह मान्य होगी अथवा संबंधित विकास खण्ड अधिकारी से चिकित्साधिकारी द्वारा आख्या प्राप्त की जानी होगी। तदोपरान्त प्रभारी चिकित्साधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वीकृति प्रदान करनी होगी। नगरीय क्षेत्र के लाभार्थी संबंधित उप मुख्य चिकित्साधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा उन्हीं के द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर स्वीकृति की जायेगी। आवेदन पत्रों के साथ बी.पी.एल. के राशन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। राशन कार्ड न होने की स्थिति में आय की जांच संबंधित उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा संबंधित तहसीलदार से करायी जायेगी। नगरीय क्षेत्र की घोषित मलिन बस्तियों में जांच डूडा के कार्यालय से भी करायी जा सकती है। आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त अधिकारियों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना की जिला समिति में सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। लाभार्थियों को धनराशि का वितरण ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य समिति की बैठक/ आर.सी. एच. कैंम्पो एवं अन्य कोई सामुहिक शिविरो जिसमें संबंधित ग्राम/ क्षेत्र के लोग भी उपस्थित हो में नगद रूप में की जायेगी।

5. लाभार्थियों की पात्रता भारत सरकार के मानक के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. लाभार्थियों की आयु 19 वर्ष से ऊपर होनी चाहिये।
2. लाभार्थी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली महिला/बी.पी.एल. राशन कार्ड धारी होगी।
3. लाभार्थी को केवल प्रथम दो जीवित प्रसव पर ही यह सुविधा अनुमन्य होगी।
4. लाभार्थी को यह सुविधा प्रसव से 8 से 12 सप्ताह पूर्व अवश्य मिल जानी चाहिये।
5. लाभार्थी की गर्भावस्था का सत्यापन उपकेन्द्र में तैनात ए.एन.एम. तथा हैल्थ पोस्ट में तैनात महिला चिकित्साधिकारी/ प्रसवोत्तर केन्द्र की महिला चिकित्साधिकारी/ जिला महिला चिकित्सालय की चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं को प्रसव से 8-12 सप्ताह पूर्व ₹500/- दिये जायेंगे।
7. योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नियमित रूप से जिला समिति द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जिला समिति उत्तरदायी होगी। मुख्य चिकित्साधिकारी योजना के लिये आवश्यकतानुसार विकासखण्ड वार मासिक एवं वार्षिक कार्यभार निर्धारित करेंगे।
8. योजना का जनपद स्तर पर वृहद प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये। इस प्रयोजन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी अपने अधीन प्रचार-प्रसार शाखा/ जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना

अधिकारी को सेवाओं का भी उपयोग करेंगे। धनराशि के आवंटन एवं व्यय की समीक्षा भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार समय-समय पर की जायेगी।

9. जिन जनपदों द्वारा अभी तक विगत वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र, आडिट रिपोर्ट एवं भारत सरकार को नहीं भेजे गये हों, उन्हें अविलम्ब भारत सरकार को भेजे जाने की कार्यवाही की जाये।

10. प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जनसंख्या की प्रजनन दर को ध्यान में रखते हुये तथा बी.पी.एल. परिवारों का प्रतिशत देखते हुये योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रत्येक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे जिसके सापेक्ष अनुश्रवण किया जायेगा।

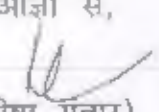
11. मुख्य चिकित्साधिकारी जोकि योजना के सदस्य-सचिव/नोडल अधिकारी भी है, के द्वारा योजना की मासिक सूचना निर्धारित प्रारूप पर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क०, उत्तरांचल को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क०, उत्तरांचल द्वारा सभी जनपदों की सूचना संकलित कर समय-समय पर शासन तथा राज्य स्तरीय समिति के सम्मुख अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

आलोक कुमार जैन
सचिव

संख्या : 16(1)/चि०-2-2002/7(चि०)/2002 टी.सी. तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क०, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निदेशक, आई.सी.डी.एस., उत्तरांचल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त कार्यक्रम अधिकारी, आई.सी.डी.एस., उत्तरांचल।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीषा पवार)
अपर सचिव